6324

Ship Building

Shrimati Tarkeshwari Sinha: Shri Raghunath Singh: Dr. Ram Subhag Singh:

Will the Minister of Transport and Communications be pleased to state:

- (a) whether Government approached some foreign countries to build ships for India on deferred payment basis;
- of the countries (b) the names approached; and
- (c) the response received from them?

The Minister of State in the Ministry of Transport and Communications (Shri Raj Bahadur): (a) No, Sir.

and (c). Do not arise.

Shrimati Tarkeshwari Sinha: I know whether, during the recent visit of the Prime Minister to European countries including Sweden, the Prime Minister discussed this aspect of the question with the Swedish Government and whether any offer was made not only on the deferred payment basis but also on cash terms basis about making the ships Sweden for India?

Shri Raj Bahadur: I suggest that question may be put to the Prime Minister.

Shrimati Tarkeshwari Sinha: It has been put to the Government and the Government must reply.

Speaker: That only that the hon. Minister who charge of it is not aware of it.

Dr. Ram Subhag Singh: He should have said so.

Mr. Speaker: To that extent there is nothing there.

श्री रघु श्र सिंह : मैं जानना चाहा। हं कि जापान से, जिसका, वर्ल्ड में जितने जहाजों का निर्माण इस समय होता है, उसमें ३० प्रतिशत हिस्सा है, सहायता लेने की कोशिश की जायेगी ?

श्री राज बहादर : हमारा इरादा यह है कि जो कोई देश भी हमको इस मामले में सहायता देना चाहता हो, उससे हम सहायता

डा॰ राम सुनग निह : क्या माननीय मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि सन १६५० से ले कर अब तक अन्न का आयात करने में कितना फेट देना पड़ा और १६५० से अब तक जहाजों को खरीदने में कितना मुल्य देना पड़ा है ?

श्री राज हादुर : इसके लिये नोटिस की ग्रावश्यकता होगी लेकिन ग्रन्दाज यह लगाया जाता है कि ७५ करोड़ से १०० करोड तक रुपया हमको अपना जो आयात श्रौर निर्यात का व्यापार है उसका किराया देने के लिये खर्च करना पड़ा है।

Shrimati Tarkeshwari Sinha: May I know the progress that has been made by the Government in regard to the purchase of the 'Liberty' ships from the United States about which there were some Press reports?

Shri Raj Bahadur: The question of acquisition of 'Liberty' ships is still under the consideration of the Government of USA and when this finalised some definite idea may given.

केन्द्रीय .र्यट ः मंत्रण : स्सिति

*५३६. श्री अक्त दर्शा: क्या परिवहन तथ संच र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

- (क) क्या केन्द्रीय पर्यटक मंत्रणा समिति भ्रौर प्रादेशिक पर्यटक मंत्रणा समितियों के पुनर्गठन के प्रश्न के सम्बन्ध में, जो कुछ समय से विचाराधीन था, ग्रन्तिम निर्णय किया जा चका है;
- (ख) यदि हां, तो क्या पुनर्गठित समितियों के सदस्यों का एक विस्तृत विवरण सभा-पटल पर रखा जायेगा; श्रौर

6325

(ग) यदि नहीं, तो उनके पुनर्गठन में विलम्ब के क्या कारण हैं ग्रौर उनका पुनर्गठन कब तक पूरा हो जायेगा ?

परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) से (ग). एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है। [देखिये परिशिष्ट २, ध्रनुबन्ध संख्या ५२]

श्री भक्त दर्शन : इस विवरण से ज्ञात होता है कि यह प्रश्न ग्रभी विचाराधीन है। इससे पहने भी इसी प्रकार के प्रश्नों का उत्तर देते हुये माननीय मंत्री ने बतलाया था कि यह प्रश्न विचाराधीन है, तो मैं जानना चाहता हूं कि इस पर कब तक विचार होता रहेगा ?

श्री राज बहादुर : मैं यह ग्रन्भव करता हूं कि पिछली बार जब यह प्रश्न उठाया गया था तब से लेकर ग्रब तक इस बीच में प्रगति ग्रवश्य हुई है ग्रौर वह इस प्रश्न के उत्तर से भी स्पष्ट है । इस बीच में जैसा कि कहा गया केन्द्रीय सलाहकार समिति की बैठक शिमला में हुई ग्रौर उसने एक निश्चित सिफारिश की है जो कि विचाराधीन है ग्रौर ग्राशा की जाती है कि इस सिफारिश के ग्रनुसार कार्य होगा । इसके ग्रतिरिक्त यह भी स्पष्ट है कि कुछ राज्य सरकारों ने ग्रपने यहां यह समितियां बनाई हैं। जिन्होंने नहीं बनाई हैं उनसे हमारी लिखा पढ़ी जारी है ।

श्री भक्त दर्शन: ग्रभी तक जो समितियां बनी हैं उनमें राज्य सरकारों के प्रतिनिधि ग्रौर इस व्यवसाय के प्रतिनिधि लिये जाते रहे हैं तो क्या गवर्नमेंट ने इस सुझाव पर भी विचार किया है कि धारा सभाग्रों ग्रौर संसद् के प्रतिनिधियों को भी उसमें रखा जाये जो उसमें खास तौर से दिलचस्पी रखते हैं?

श्री राज बहादुर : उस समिति में संसद्कै सदस्य श्री बी० शिवा राव थे लेकिन जहां तक मुझे मालूम है वे बहुधा उसकी बैठकों में शामिल नहीं हो सके ।

Shri Narayanankutty Menon: May I know whether the Government is aware that no tourist office is opened anywhere in Kerala and also that the Central tourist office is not at all giving information regarding the places of interest? Secondly, does it know that the tourists coming to India and desirous of going to that place are put to large inconvenience?

Shri Raj Bahadur: That is a suggestion for action which I will bear in mind very gladly.

Shri Narayanankutty Menon: That is a specific question—is there any branch open in Kerala? Is the Central office supplying any information?

The Minister of Transport and Com-(Shri Lal Bahadur munications Shastri): It is upto the State Government to open tourist offices. Government of India opens tourist offices. There are many States which have already started working a number of tourist offices in the States and I am somewhat surprised that the Kerala Government has not taken any step so far. As regards the establishment of regional office there, we will have to consider it in the context of our Second Plan.

Shri Narayanankutty Menon: My second part has not been answered—why the Central tourist office does not publish any information on places of interest?

Shri Lal Bahadur Shastri: We will be very glad to do so. The State Government has simply to ask for it. But, I do not know some literature must have been published but I cannot say offhand. I am quite positive that a word from the State Government would give them enormous literature as much as they want.

Shri Ramanathan Chettiar: May I know whether the Central Tourist Advisory Committee and the Regional Tourist Advisory Committees do really perform some useful work to help

6328

tourism in this country or they are merely glorified bodies?

Oral Answers

Mr. Speaker: This question need not be answered. It is for obtaining information that the hon. are allowed this hour so that they may elicit information. There are other opportunities and occasions for saying things like that. Next ques-

Railway Parcels

*540. Shri Bibhuti Mishra:

Will the Minister of Railways pleased to state:

- (a) whether it is a fact that Government have introduced a system namely 'Tell-Tale' labels on railway parcels as an experimental measure to facilitate enquiry into case of delay in transit and adoption of remedial measures in the third-week of June, 1957; and
- (b) if so, how far it has proved fruitful?

The Deputy Minister of (Shri Shahnawaz Khan): (a) an arrangement has been introduced on a trial basis between selected pairs of stations on the Eastern Southern Railways from 1-3-57 and on the North-Eastern, Eastern South-Eastern Railways from 1-7-57.

(b) It is too early yet to assess the usefulness of this experiment.

श्री विभ्रत मिश्र : मैं यह जानना चाहता हं कि इतने समय के अन्दर सदनं रेलवे में ग्रौर खास करके पूर्वोत्तर रेलवे में पैकेज़ेज के डिले के कितने केसेज हुए हैं ?

श्री शक्हनबाज खां: जिस एक जगह पर यह तजुर्बा किया जा रहा है उसके भ्रन्दाज को एनालाइज किया गया है श्रीर उससे पता चला है कि थोर्ड़ बहुत देर होती है । मैं उसकी कुछ तफसील दे दूं। सदनं रेलवे ने ६४ पैकेजेज के बारे में एनालिसिस की थी

३१ पैकेजेज तो ठीक वक्त पर पहुंच गये, ५० एक, दो दिन की देर करके पहुंचे और १३ ऐसे थे जो तीन दिन की देर से पहुंचे।

श्री विभृति मिश्र : मैं जानना चाहता हं कि पूर्वोत्तर रेलवे में उनका क्या अनुभव रहा है, पूर्वोत्तर रेलवे में मुकामाघाट जो वहां का बौटेलनक है वहां के बारे में क्या वे कुछ बतलायेंगे ?

श्री शाहनवाज खां: जिस वक्त यह चीज तैयार हो जायेगी तो बतला दिया जायेगा ।

Shri Heda: May I know whether the information is recorded on the label itself or is taken to some register at different points so that it may be checked up?

Shri Shahnawaz Khan: For the time being, it is being entered on the label itself and only ten per cent of the packages are marked.

श्री फीरोज गांधी: क्या मंत्री जी को इस बात की इतिला है कि स्टेशन मास्टर लोग लेबिल काट कर दूसरा ग्रपना लेबिल लगा करके ग्रफसरों को यह पार्सल भेज दिया करते हैं ?

Mr. Speaker: The hon. Member is suggesting a way.

Shri Feroze Gandhi: That means that the hon. Minister has not read the Kripalani Report on corrup-

The Minister of Railways Jagjivan Ram): At that time, these labels were not in force.

Shri Feroze Gandhi: Ordinary labels.

Shri Heda: The Minister has said that information is recorded only on the labels. May I know if the Government has thought of a contingency when the label along with the parcel is lost?